



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]
No. 253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2008/वैशाख 19, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2008/VAISAKHA 19, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

सं. 64/2008-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 349(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल को,-

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतनी सीमा शुल्क से, जो मूल्य के तीन प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है;

(ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है, जब आयातक द्वारा विशेष रूप से दावा किया गया हो।

2. इस अधिसूचना के तहत छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात:-

(1) यह कि आयातित माल, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 के निबंधनों के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के अधीन जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा तीन प्रतिशत शुल्क की दर से माल का आयात अनुज्ञात किया गया है और उक्त अनुज्ञप्ति/प्राधिकार निकासी के समय उचित सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा विकलन के लिए प्रस्तुत की जानी है;

परन्तु उक्त सारणी की क्रम संख्या 4 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्य अवधि वह अवधि मानी जाएगी जो संपूर्ण निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए अनुज्ञात की गई हो;

यह भी शर्त है कि मोटर कारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों/सभी उद्देश्यों वाले वाहनों के आयात की अनुमति केवल होटलों, ट्रवेल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों या टूर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और गोल्फ रिसोर्ट्स के स्वामित्व/संचालन वाली कंपनियों को ही निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:

- (i) होटल, ट्रेवल और टूरिज्म तथा गोल्फ टूरिज्म सेक्टर से चालू वर्ष में और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन 1.5 करोड़ रु. या इससे अधिक हो;
- (ii) किसी लाइसेंसिंग वर्ष में मोटर कारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों/सभी उद्देश्यों वाले वाहनों के आयात के लिए जारी सभी ई पी सी जी प्राधिकारों पर शुल्क में बचत की गयी धनराशि होटल, ट्रेवल्स एवं टूरिज्म एवं गोल्फ टूरिज्म सेक्टरों में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में अर्जित औसत विदेशी मुद्रा के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए; और
- (iii) आयातित वाहन का पंजीकरण इस प्रकार होगा कि वाहन का प्रयोग केवल टूरिज्म के उद्देश्य के लिए हो। आयात की तारीख से 6 माह के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति वाहन के आयात की पुष्टि के रूप में संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा की जाएगी।

यह भी शर्त है कि इस अधिसूचना के तहत आधुनिक अव-संरचना निर्माण के उद्देश्य से रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का लाभ केवल उन्हीं खुदरा विक्रेताओं को दिया जाएगा, जिसके पास न्यूनतम क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर हो।

(2) यह कि निर्यात की बाध्यताएं पूरी होने तक आयातित माल को बिक्री/पट्टे या किसी और तरीके, से निस्तारित या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(3) यह कि आयातक लाइसेंस या प्राधिकार जारी होने की तारीख से 8 वर्ष की अवधि के भीतर सीमा शुल्क उपायुक्त एवं सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रपत्र पर और प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित ऐसी धनराशि का बांड भरेगा जो उसे एफ ओ बी आधार पर लाइसेंस या प्राधिकार में विनिर्दिष्ट आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के 8 गुने के बराबर या ऐसी अधिक धनराशि जो हैंडबुक क्रियाविधि खंड-1 के पैरा 5.10 के निबंधनों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाए, निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए निम्नलिखित अनुपात में बाध्य करें, नामशः-

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1	2	3
1	पहले से छठे वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
2	सात से आठ वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु जहां बचाया गया शुल्क 100 करोड़ रुपये से कम न हो अथवा जहां कृषि निर्यात जोन में इकाइयों को लाइसेंस जारी किया जाता है, जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाता है, वहां निर्यात बाध्यता लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के भीतर निम्न अनुपातों में पूरी की जाएगी, अर्थातः-

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1	2	3
1	एक से 10 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
2	11 से 12 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु यह कि जहां कोई रूग्ण इकाई औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अधिसूचित है अथवा जहां रूग्ण इकाई के संबंध में इसके पुनर्संजीवन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई पुनर्वास स्कीम घोषित की जाती है, वहां निर्यात बाध्यता पुनर्वास पैकेज के अनुसार पूरी की जाएगी या यदि पुनर्वास पैकेज में समायावधि विनिर्दिष्ट नहीं है तो 12 वर्षों में।

बशर्ते कि जहां पूंजीगत माल का आयात कृषि इकाइयों और छोटे और कुटीर उद्योग क्षेत्र के लिए किया जाता है, वहां पर निर्यात बाध्यता आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के छह गुने के बराबर जैसाकि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है, निश्चित की जाएगी, या ऐसी उच्चतर राशि के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को जारी किए जाने की तारीख से 12 वर्ष के भीतर निश्चित की जाएगी।

यह भी शर्त है कि जहां पूंजीगत माल का विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.10 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए आयात किया जाता है या विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.1 में परिभाषित लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए, जैसा भी मामला हो, आयात किया जाता है, वहां निर्यात बाध्यता लाइसेंस/प्राधिकार में यथा विनिर्दिष्ट आयातित माल पर बचाए गए शुल्क से 6 गुने के बराबर लाइसेंसिंग प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अथवा लाइसेंस प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अधिक धनराशि की निर्यात बाध्यता लाइसेंस जारी होने के आठ वर्ष के भीतर निश्चित की जाएगी। आगे शर्त है कि एस एस आई इकाइयों के मामले में इस योजना के अंतर्गत ऐसे आयातित पूंजीगत माल की लैंडेड सी आई एफ मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होगा और ऐसे आयात के बाद संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश एस एस आई सीमा से अधिक नहीं होगा।

परन्तु किसी विशिष्ट ब्लॉक वर्ष की निर्यात बाध्यता को पूर्ववर्ती ब्लॉक में किए गए अधिक निर्यातों द्वारा मंजूर किया जा सकेगा;

(4) यह कि यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के संबंध में छूट का दावा नहीं करता है, तो उसे निर्यात बाध्यता के परिगणन के संबंध में बचाई गई शुल्क राशि के संगणन के प्रयोजनार्थ उक्त सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने संबंधी लाभ उठाने वाला नहीं समझा जाएगा बशर्ते अतिरिक्त शुल्क अदा करने का सेनवैट क्रेडिट न लिया गया हो;

(5) यह कि आयातकर्ता, अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से प्रत्येक ब्लॉक की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त को समाधानप्रद रूप में पूरी की गई निर्यात बाध्यता का परिणाम दर्शित करने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जहां किसी विशिष्ट ब्लॉक की निर्यात बाध्यता पूर्ववर्ती शर्त के निबंधनों के अनुसार पूरी नहीं की गई है, वहां आयातकर्ता, उक्त ब्लॉक की समाप्ति से तीन मास के भीतर उतनी रकम का, जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग के बराबर का जिसका वही अनुपात है जो निर्यात बाध्यता को पूरा न किया गए भाग का कुल निर्यात बाध्यता से है, माल की निकासी की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित संदाय करेगा;

(6) जहां आयातकर्ता शर्त (3) में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता की अवधि की आधी अवधि में शर्त (3) में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता का 75% या उससे अधिक पूरी करता है, उसकी शेष निर्यात बाध्यता माफ कर दी जाएगी और यह माना जाएगा कि उसने सारी निर्यात बाध्यताएं पूरी कर दी हैं।

(7) यह कि आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल आयातकर्ता के कारखाने या परिसर में संस्थापित किए जाते हैं और अधिकारिता वाले यथा-स्थिति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त से आयातकर्ता के कारखाने या परिसरों में पूंजी माल के संस्थापन और उपयोग की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण-पत्र आयात पूरा होने की तारीख से छह मास से भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें, यथास्थिति प्रस्तुत किया जाता है:-

बशर्ते पुर्जों के आयात के मामले में, स्थापना प्रमाणपत्र आयात की तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

आगे शर्त यह है कि यदि आयातक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पंजीकृत नहीं है या वह कोई सेवा प्रदान करने वाला है, तो वह किसी स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी संस्थापन और प्रयोग का उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है;

बशर्ते कि आगे निम्नलिखित के संबंध में,-

- (i) ऐसा विनिर्माता निर्यातकर्ता और वणिक निर्यातकर्ता जिसका समर्थक विनिर्माता/विक्रेता हो;
- (ii) कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए संविदा कृषि में उपयोग के लिए सिंचाई उपस्करों का आयात; और
- (iii) इम्पोर्टर रेडरिंग सर्विसेज,

पूँजीगत माल, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति (यों) के कारखाने में या परिसर में संस्थापित किया जा सकेगा जिसका नाम और पता शर्त (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति पर या प्राधिकार पर और शिपिंग बिल पर भी पृष्ठंकित किया गया है और जहां आयातकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा शुल्क के पूर्ण अंतर के लिए बंधपत्र, शर्त (3) के निबंधनानुसार जहां-कहीं आवश्यक है, बैंक प्रतिभूति सहित निष्पादित किया गया है और ऐसे विनिर्माता या अन्य व्यक्ति निर्यात बाध्यता को और इस अधिसूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के लिए और व्यतिक्रम की दशा में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज सहित शुल्क का संदाय करने के लिए स्वयं को संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से आबद्ध करते हैं;

बशर्ते कृषि निर्यात जोन में स्थित एगो इकाईयों के लिए सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्राधिकारिक उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सहायक उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सूचित करते हुए कृषि निर्यात जोन के अंदर पूँजीगत माल को ले जा सकता है, यथास्थिति इस शर्त के अधीन कि ऐसी गतिविधियों का आयातक सही रिकार्ड रखेगा।

(8) यह कि आयात और निर्यात मुम्बई, कोलकाता, कोचिन, मगडल्ला, काकीनाडा, कांडला, मंगलोर, मर्मगोवा, चेन्नै, न्हावा शेवा, पारादीप, पिपावव, सिक्का, ट्यूटीकोरीन, विशाखापत्तनम, दहेज, मुंधा, नागापट्टीनम, ओरवा, बेडी(रोजी जामनगर सहित), मुलद्वारका, पोरबंदर, धर्मतार, वाडीनार और हल्दिया (कोलकाता बंदरगाह का हल्दिया डोक परिसर) के समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से अथवा अहमदाबाद बंगलोर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, चेन्ने, श्रीनगर, तिरुबंदरूम, वाराणसी, नागपुर, कोचिन, राजसांसी(अमृतसर), लखनऊ (अमौसी), इंदौर और डाबोलीम (गोवा) के किसी विमानपत्तन के माध्यम से अथवा आगरा, बंगलोर, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहाटी, गुंटुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, मोरादाबाद, नागपुर, पिम्प्री(पुणा), पितमपुर (इंदौर), सुरत, तिरुपुर, वाराणसी, नासिक, रुद्रपुर(नैनीताल), दिधी (पुणा), वडोदड़ा, दौलताबाद (वांझारवाडी और मालीवाडा), वलुज (औरंगाबाद), अनापार्थी (आंध्रप्रदेश) सलेम, मालनपुर, सिंगापुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाडी, मदुरई, भिलवाडा, पांडीचेरी, गरही, हसूर, भतिंडा, डाप्पर(डैरा बस्सी), छेहराता (अमृतसर), कसर, मिराज, रेवाडी, मुसावल, जमशेदपुर, सूरजपुर, दादरी, ट्यूटीकोरीन, कुंडली, भदोही, राजपुर, मंडीदीप (जिला रायसेन) दुर्गापुर (निर्यात प्रोन्नयन औद्योगिक पार्क), बाबरपुर और लोनी (जिला गाजियाबाद) के किसी भी इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा रानाघाट, सिंघाबाद, रक्सौल, जोगबनी, नौटानवा(सोनौली), पेट्रापोल, महादीपुर, नेपालगंज रोड, दाव की, अगरतला, सुतारखांडी, अमृतसर रेल कार्गो, अट्टारी रोड, हिल्ली, धोजाडांगा और छंगबांधा स्थित किसी भी लैंड कस्टम स्टेशन के माध्यम से अथवा विशेष आर्थिक जोन, अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अंतर्गत अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किया जाता है।

यह प्रावधान है कि सीमा शुल्क आयुक्त विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा लैंड कस्टम स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(9) उपर्युक्त शर्त (5) में कुछ भी अंतर्विष्ट हो, जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी किसी भी ब्लॉक के लिए ब्लॉक क्रम में अवधि बढ़ाने अथवा दो वर्षों की अवधि तक निर्यात देयता को पूरा करने की कुल अवधि अथवा निर्यात देयता में कमी को नियमित करने के लिए अधिकतम ऐसी निर्यात देयता के पाँच प्रतिशत तक, अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है वहाँ निर्यात देयता की उक्त ब्लॉक क्रम में अवधि अथवा कुल अवधि को सीमा शुल्क के उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, द्वारा बढ़ाया/माफ किया जा सकता है:

यह प्रावधान है कि शर्त (3) के दूसरे परन्तुक में उल्लिखित बीमार इकाईयों के संबंध में निर्यात देयता की कुल अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

यह भी प्रावधान है कि यदि प्राधिकार धारी निर्यात देयता के पूरा नहीं किए गए अंश पर पचास प्रतिशत अंतर शुल्क का भुगतान करता है और इसके लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करने पर सहमत होता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात देयता की कुल अवधि को दो और वर्षों की अवधि तक बढ़ा सकता है।

3. जहाँ उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट माल दोषपूर्ण अथवा इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त पाये जाते हैं तो उक्त माल को उनके आयात पर शुल्क के भुगतान की तिथि से तीन वर्षों के अंदर विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस पुनर्निर्यात किया जा सकता है।

यह प्रावधान है कि पुनर्निर्यात के समय सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा मामला हो, की संतुष्टि के लिए माल की आयात किए गए माल के रूप में पहचान की जाती है।

4. निर्यात देयता की छूट पर वहाँ विचार किया जा सकता है जहाँ अति प्राकृतिक अथवा अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों/कारणों, जो निर्यातक के नियंत्रण के बाहर हैं (जैसे अंतर्राष्ट्रीय कीमते, प्रौद्योगिकी अप्रचलन आदि) के कारण निर्यातक निर्यात देयता को पूरा करने में असमर्थ है। ऐसे अनुरोधों पर विचार वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों वाली समिति द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय के अंतर्गत किया जाएगा। समिति के निर्णय को राजस्व विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए-

- (1) 'कारखानागत माल' का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.12 में दिया गया है।
- (2) 'निर्यात देयता'-

(i) का अर्थ है आयातक पर भारत से बाहर उत्पादित/उत्पादन के लिए सक्षम अथवा इस अधिसूचना के दृष्टिकोण से आयातित कारखानागत माल के उपयोग द्वारा दी गई सेवा पर देयता। निर्यात देयता बढ़ाई गई अवधि यदि कोई हो, सहित कुल निर्यात देयता अवधि के अंतर्गत उन्हीं उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आयातक द्वारा प्राप्त निर्यात के औसत स्तर के अलावा होगी। ऐसी औसत उन्हीं उत्पादों के लिए विगत 3 वर्षों में निर्यात निष्पादन का गणितीय औसत होगा।

यह प्रावधान है कि निर्यात देयता के पचास प्रतिशत को आयातक अथवा ई पी सी जी प्राधिकार वाले ग्रुप कम्पनी/ प्रबंधित होटल द्वारा उत्पादित अन्य माल अथवा प्रदान की गई सेवा के निर्यात द्वारा भी पूरा किया जा सकता है, परन्तु इस शर्त के अधीन कि ऐसे मामलों में लगाई गई अतिरिक्त निर्यात देयता पिछले तीन वर्षों में आयातक अथवा उसके ग्रुप कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा प्राप्त औसत निर्यात के अलावा होगी।

यह भी प्रावधान है कि हस्तशिल्प, हैंडलूम, झोपड़ी, छोटे क्षेत्र, कृषि, एक्वा-कल्चर, पशु पालन, पुष्पकृषि, बागबानी, मत्स्यपालन, द्राक्ष-कृषि, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन से संबंधित माल के निर्यात के मामले में आयातक द्वारा निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा।

यह भी प्रावधान है कि इस अधिसूचना के अंतर्गत आयातित औजारों को छोड़कर माल को आयात की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी, उन मामलों में भी नहीं जहाँ निर्यात देयता पूरी कर ली गई हो। तथापि, कारखानागत माल को निर्यात देयता पूरी करने के बाद परन्तु आयात की तिथि से पाँच वर्षों के अंदर क्षेत्रीय प्राधिकारी और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचना देते हुए ग्रुप कम्पनियों के बीच अंतरित करने की अनुमति होगी।

यह भी प्रावधान है कि पुराने यू एस एस आर अथवा दिनांक 31.3.08 तक डी जी ए फटी द्वारा अधिसूचित देशों को किए गए निर्यात को निर्यात के औसत स्तर निर्धारित करने के लिए गिना नहीं जाएगा।

यह भी प्रावधान है कि ऐसे माल जिन पर विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत पुरस्कार स्कीमों के लाभ लिए गए हों, को निर्यात देयता पूरी करने के लिए गिना नहीं जाएगा।

यह भी प्रावधान है कि केवल ऐसे शिपिंग बिलों के लिए निर्यात को निर्यात देयता को पूरा करने के लिए गिना जाएगा जिन पर ई पी सी जी प्राधिकार सं. और तिथि का उल्लेख होगा।

(ii) को वास्तविक निर्यात के जरिए पूरा किया जाएगा और निर्यात प्राप्ति को आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल किया जाएगा। तथापि निम्नलिखित संवर्गों की आपूर्तियों को निर्यात देयता पूरी करने के लिए गिना जाएगा:

(क) सम निर्यात नामतः

- (1) अग्रिम प्राधिकारी वार्षिक आवश्यकता/डी एफ आई ए के लिए अग्रिम प्राधिकार के संबंध में माल की आपूर्ति;
- (2) ई ओ यू अथवा एस टी पी अथवा ई एच टी पी अथवा बी टी पी को माल की आपूर्ति;
- (3) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई सी बी) के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त पोषित

1709 GI/08-2

- परियोजनाओं को माल की आपूर्ति, वहाँ विधिक करारों में सीमा शुल्क को शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन का प्रावधान है; आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आई सी बी के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल और उपस्करों (प्रमुख ठेकों की एकमात्र जिम्मेदारी) की आपूर्ति तथा उन्हें लगाना जहां बोलियाँ विदेश में उत्पादित माल के लिए डेलीवरी ड्यूटी पेड़ (डी डी पी) कीमतों के आधार पर आमंत्रित कर मूल्यांकन किया गया जाता हो;
- (4) किसी भी ऐसी परियोजना अथवा उद्देश्य के लिए माल की आपूर्ति जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय अधिसूचना द्वारा शून्य सीमा शुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान करता है और आपूर्ति आई सी बी प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है;
- (5) आई सी बी प्रक्रिया के अंतर्गत उपर्युक्त (4) में शामिल नहीं की गई उर्जा परियोजनाओं और रिफाईनरियों को

माल की आपूर्ति;

- (6) आई सी बी के प्रतिकूल प्रतियोगी बोलियों के माध्यम से न्यूक्लियर उर्जा परियोजनाओं को माल की आपूर्ति;
- (ख) घरेलू टेरिफ क्षेत्र को आई टी ए-1 मर्चों की आपूर्ति बशर्ते कि सरल विदेशी विनिमय वाली मुद्रा में वसूली हो;
- (ग) आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान एवं आर एंड डी सेवाओं के लिए प्राप्त विदेशी विनिमय; और
- (घ) विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 9 के दृष्टिकोण से पोर्ट हैंडलिंग सेवाओं के लिए रूप में प्राप्त भुगतान ।
- (3) " विदेश व्यापार नीति" का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/2004, दिनांक 31 अगस्त, 2004 के जरिए प्रकाशित विदेश व्यापार नीति 2004-2009;
- (4) " लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी" का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस अथवा प्राधिकार प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी;
- (5) "उत्पादन" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944(1944 का 1) की धारा (2) के खंड (घ) में परिभाषित किया गया है।

सारणी

क्र.सं.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	सेकेंड हैंड कारखानागत माल सहित उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन के पश्चात् कारखानागत माल
2.	आयातक द्वारा कारखानागत माल के रूप में एसेम्बल करने के लिए एस केडी/सी केडी में कारखानागत माल
3.	लोप किया गया
4.	ऐसे आयातित, एसेम्बलड अथवा उत्पादित कारखानागत माल के रख-रखाव के लिए वास्तव में आयातित और अपेक्षित क्रम.सं.1 और 2 में विनिर्दिष्ट माल के खुले पूर्ण
5.	लाइसेंस अथवा प्राधिकार धारी के वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के लिए खुले पूर्ण
6.	मोटर कार/स्पोर्ट्स यूटिलिटी वेहिकल्स/आल परपस वेहिकल्स

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2008

F. No. 64/2008-CUSTOMS

G.S.R. 349(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Table annexed hereto, from,-

- (i) so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of three percent ad-valorem, and
- (ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, when specifically claimed by the importer.

2. The exemption under this notification shall be subject to the following conditions, namely :-

- (1) that the goods imported are covered by a valid licence or valid authorization issued under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of Chapter 5 of the Foreign Trade Policy permitting import of goods at the rate of three percent duty and the said licence or authorization is produced for debit by the proper officer of customs at the time of clearance :

Provided that for import of spare parts specified at Sr.No.4 of the said Table, the validity period of the licence or authorization shall be deemed to be the period permitted for fulfillment of the export obligation in full :

Provided further that the import of motor cars, sports utility vehicles or all purpose vehicles shall be allowed only to hotels, travel agents, tour operators or tour transport operators and companies owning or operating golf resorts, subject to the condition that,-

- (i) the total foreign exchange earning from hotel, travel and tourism and golf tourism sectors in current and preceding three licensing years is Rs.one crore fifty lakhs or more;
- (ii) the duty saved amount on all EPCG authorizations issued in a licensing year for import of motor cars, sports utility vehicles or all purpose vehicles shall not exceed 50% of average foreign exchange earnings from hotel, travel and tourism and golf tourism sectors in preceding three licensing years; and
- (iii) the vehicles imported shall be so registered that the vehicle is used for tourist purpose only. A copy of the registration certificate shall be submitted to the concerned Customs authorities as a confirmation of import of vehicle within six months from the date of import:

Provided also that the benefit of import of capital goods at concessional duty under this notification for creation of modern infrastructure shall be extended only to such retailers who have a minimum area of 1000 square meters.

(2) that the goods imported shall not be disposed of or transferred by sale or lease or any other manner till export obligation is completed.

(3) that the importer executes a bond in such form and for such sum and with such surety or security as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs binding himself to fulfill export obligation on FOB basis equivalent to eight times the duty saved on the goods imported as may be specified on the licence or authorization, or for such higher sum as may be fixed or endorsed by the Licensing Authority or Regional Authority in terms of Para 5.10 of the Handbook of Procedures Vol I, within a period of eight years from the date of issue of licence or Authorization, in the following proportions, namely :-

S.No. Period from the date of issue of licence Proportion of total export obligation

(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1 st to 6 th year	50%
2.	Block of 7 th to 8 th year	50%

Provided that where the duty saved is not less than Rupees one hundred crores, or where the licence or authorization is issued to units in the agri export zone as may be notified by the licensing authority or Regional Authority, the export obligation shall be fulfilled within a period of twelve years from the date of issue of licence in the following proportions, namely :-

S.No. Period from the date of licence Proportion of total export obligation

(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1 st to 10 th years	50%
2.	Block of 11 th to 12 th year	50%

Provided further that where a sick unit is notified by the Board for Industrial and Financial Reconstruction or where a rehabilitation scheme is announced by the concerned State Government in respect of sick unit for its revival, the export obligation may be fulfilled within time period allowed as per the rehabilitation package or twelve years, if the time period is not specified in the rehabilitation package:

Provided also that where the capital goods are imported by agro units and units in tiny and cottage sector, the export obligation shall be fixed equivalent to six times the duty saved on the goods imported as may be specified on the licence, or for such higher sum as may be fixed by the licensing authority, within a period of twelve years from the date of issue of the licence or authorization :

Provided also that where the capital goods are imported for technological upgradation as per conditions specified in Para 5.10 of the Foreign Trade Policy or by small scale industry units as defined in paragraph 5.1 of the Foreign Trade Policy, as the case may be, the export obligation shall be fixed equivalent to six times the duty saved on the goods imported as may be specified on the licence or authorization, or for such higher sum as may be fixed by the Licensing Authority or Regional Authority, within a period of eight years from the date of issue of licence subject to the further condition that in the case of Small Scale Industry (SSI) units the landed CIF value of such imported capital goods under the scheme shall not exceed Rupees fifty lakhs and total investment in plant and machinery after such imports shall not exceed the SSI limit :

Provided also that export obligation of a particular block may be set off against the excess exports made in the said preceding block(s);

(4) that if the importer does not claim exemption from the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, the additional duty so paid by him shall not be taken for computation of the net duty saved for the purpose of fixation of export obligation provided the Cenvat credit of additional duty paid has not been taken;

(5) that the importer produces within 30 days from the expiry of each block from the date of issue of licence or authorization or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow, evidence to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs showing the extent of export obligation fulfilled, and where the export obligation of any particular block is not fulfilled in terms of the preceding condition, the importer shall within three months from the expiry of the said block pay duties of customs of an equal amount equal to that portion of duties leviable on the goods, but for the exemption contained herein which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation together with interest at the rate of 15% per annum from the date of clearance of the goods;

(6) where the importer fulfills 75% or more of the export obligation as specified in condition (3) within half of the period specified for export obligation as mentioned in condition (3), his balance export obligation shall be condoned and he shall be treated to have fulfilled the entire export obligation;

(7) that the capital goods imported, assembled or manufactured are installed in the importer's factory or premises and a certificate from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, is produced confirming installation and use of capital goods in the importer's factory or premises, within six months from the date of completion of imports or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;

Provided that in case of import of spares, the installation certificate shall be produced within three years from the date of import;

Provided further that if the importer is not registered with central excise or if he is a service provider, as the case may be, he may produce the said certificate of installation and usage issued by an independent Chartered Engineer;

Provided further that in the case of,-

- (i) manufacturer exporter and merchant exporter having supporting manufacturer(s) or vendor(s);
- (ii) import of irrigation equipment for use in contract farming for export of agricultural products; and
- (iii) importer rendering services;

the capital goods may be installed at the factory or premises of such other person whose name and address are endorsed on the licence or authorization referred to in condition (1) and also on the shipping bills and where the bond for full difference of duty, if necessary, in terms of condition (3) with or without a bank guarantee, as the case may be, is executed by the importer and such other person binding themselves jointly and severally to fulfill the export obligation and all other conditions of this notification and to pay duty with interest at the rate of 15% per annum in case of default;

Provided also that agro units located in Agri Export Zones or service providers in Agri export Zones may move the capital goods within the Agri Export Zones under intimation to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central

1709 GE/08-3

Excise, as the case may be, subject to the condition that the importer shall maintain accurate record of such movement;

(8) that the imports and exports are undertaken through sea ports at Mumbai, Kolkata, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagao, Chennai, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Mundhra, Nagapattinam, Okha, Bedi (including Rozi-Jamnagar), Muldwarka, Porbander, Dharamtar, Vadinar, and Haldia (Haldia Dock Complex of Kolkata port), or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Chennai, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur, Cochin, Rajasansi (Amritsar), Lucknow (Amausi), Indore and Dabolim (Goa), or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthi (Andhra Pradesh), Salem, Malanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry, Garhi Harsaru, Bhatinda, Dappar (Dera Bassi), Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj, Rewari, Bhusawal, Jamshedpur, Surajpur, Dadri, Tuticorin, Kundli, Bhadohi, Raipur, Mandideep (District Raisen), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Babarpur and Loni (District Ghaziabad) or through the Land Customs Station at Ranaghat, Singhabad, Raxaul, Jogbani, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Mahadipur, Nepalganj Road, Dawki, Agartala, Sutarkhandi, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Hilli, Ghojadanga and Changrabandha or a Special Economic Zone as notified under the Special Economic Zone, Act, 2005 (28 of 2005).

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through a land customs station.

(9) notwithstanding anything contained in condition (5) above, where the Licensing Authority or Regional Authority grants extension of block-wise period for any block(s) or overall period of fulfilment of export obligation upto a period of two years or regularization of shortfall in export obligation, not exceeding five percent of such export obligation, the said block-wise period or overall period of export obligation shall be extended or condoned by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be.

Provided that in respect of sick units referred to in the second proviso to condition (3) extension of overall period of export obligation shall not be allowed :

Provided further that the Regional Authority may grant further extension in the overall period of export obligation upto a period of further two years if the authorization holder pays fifty percent differential duty on the unfulfilled portion of export obligation and agrees to fulfill other conditions as may be specified by the Regional Authority for this purpose:

3. Where the goods specified in the said Table are found defective or unfit for use, the said goods may be re-exported back to the foreign supplier within three years from the date of payment of duty on the importation thereof:

Provided that at the time of re-export, the goods are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the goods which were imported.

4. Waiver of Export Obligation may be considered where, because of force majeure or other unforeseen circumstances/ reasons which are beyond the control of the exporter (like steep fall in international prices, technological obsolescence etc.), the exporter is unable to fulfill export obligation. Such requests shall be considered by a Committee comprising representative(s) of Department of Commerce and Department of Revenue under the Directorate General of Foreign Trade. Decision of this Committee shall be implemented by the Department of Revenue.

Explanation – For the purpose of this notification,-

(1) "Capital goods" has the same meaning as assigned to it in Paragraph of 9.12 of the Foreign Trade Policy;

(2) "Export obligation", -

(i) means obligation on the importer to export to a place outside India, goods manufactured or capable of being manufactured or services rendered by the use of capital goods imported in terms of this notification. The export obligation shall be over and above the average level of exports achieved by the importer in the preceding three licensing years for the same and similar products within the overall export obligation period including the extended period, if any. Such average shall be the arithmetic mean of export performance in the last 3 years for the same and similar products.

Provided that upto 50% of the export obligation may also be fulfilled by export of other good(s) manufactured or service(s) provided by the importer or his group company or managed hotel, which has the EPCG authorization subject to the condition that in such cases, additional export obligation imposed shall be over and above the average exports achieved by the importer or his group company or managed hotel in preceding three years for both the original and the substitute product(s) / service(s) :

Provided further that in case of export of goods relating to handicraft, handlooms, cottage, tiny sector, agriculture, aqua-culture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and sericulture, the importer shall not be required to maintain the average level of exports :

Provided also that the goods, excepting tools, imported under this notification by the aforesaid sectors, shall not be allowed to be transferred for a period of five years from the date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled. Transfer of capital goods would, however, be permitted within the group companies, after fulfillment of export obligation but before five years from the date of imports, under intimation to Regional Authority and jurisdictional Central Excise Authority :

Provided also that exports made to former USSR, or to such countries as notified by Director General of Foreign Trade as on 31.3.08, shall not be counted for fixing the average level of exports :

Provided also that the goods on which benefits of reward schemes under chapter 3 of the Foreign Trade Policy are taken shall not be counted towards the fulfillment of the export obligation :

Provided also that exports against only such shipping bills which mention the EPCG authorization No. and date shall be counted for the discharge of the export obligation;

(ii) shall be fulfilled through physical exports and the export proceeds shall be realized in freely convertible currency. However the following categories of supplies, shall also be counted towards fulfillment of export obligation:

(a) deemed exports, namely:

(1) supply of goods against Advance Authorization/Advance Authorization for Annual Requirement/ Duty Free Import Authorization (DFIA);

(2) supply of goods to Export Oriented Units (EOUs) or Software Technology Parks (STPs) or Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs) or Bio-Technology Parks (BTPs);

(3) supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance (MOF) under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those agencies or Funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty; supply and installation of goods and equipments (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by DEA, MOF under ICB, in accordance with procedures of those agencies/Funds, where bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivery Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;

(4) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty and the supply is made under ICB procedure;

(5) supply of goods to power projects and refineries not covered in (4) above under ICB procedure;

(6) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to ICB.

a. Supply of ITA-1 items to Domestic Tariff Area, provided realization is in free foreign exchange;

b. Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for Research & Development (R&D) services; and

c. Payments received in rupee terms for port handling services in terms of chapter 9 of the Foreign Trade Policy.

(3) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2004-2009 published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, No. 1/2004 dated the 31st August, 2004 as amended from time to time;

(4) "Licensing Authority or Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant a licence or authorization under the said Act;

(5) "manufacture" has the same meaning as defined in clause (f) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

Table

S.No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Capital goods for pre-production, production and post production including second hand capital goods.

2.	Capital goods in Semi Knocked Down (SKD) / Completely Knocked Down (CKD) conditions to be assembled into capital goods by the importer.
3.	Spare parts of goods specified at Serial Nos.1 and 2 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured.
4.	Spare parts for the existing plant and machinery of the licence or authorization holder.
5.	Motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles.

[F.No. 605/23/2008-DBK]

JAGMOHAN SINGH, Under Secy.

1709 GI/08-4